

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 108

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है

बिहार में कम विद्युत उत्पादन क्षमता

* 108. श्री एनके0 सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि बिहार में 493 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता देश में सबसे कम है ;
- (ख) क्या राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता के कम होने के कारण यह राज्य अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यतः केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन पर निर्भर है;
- (ग) क्या विद्युत की 2500 मेगावाट की अधिकतम मांग की तुलना में इसकी अधिकतम उपलब्धता केवल 1000 मेगावाट ही है, जिससे राज्य में लगभग 1500 मेगावाट की कमी हो रही है;
- (घ) क्या इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

बिहार में कम विद्युत उत्पादन क्षमता के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 05.03.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 108 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क): जी, नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में बिहार की अपेक्षा कम संस्थापित उत्पादन क्षमता वाले राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र हैं।

(ख): जी, हां।

(ग) 2012-13 (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान 2,295 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की तुलना में 1,784 मेगावाट उपलब्धता थी, जिसमें 511 मेगावाट की कमी है।

(घ) और (ड.): विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य में इसकी आपूर्ति एवं वितरण का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों / राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का होता है। भारत सरकार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सी जी एस) की स्थापना द्वारा राज्य के प्रयासों का अनुपूरण करती है। भारत सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बिहार राज्य में विद्युत की आपूर्ति को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) बिहार को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत आबंटन 1,264 मेगावाट (31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार) से बढ़कर 1,836 मेगावाट (31 जनवरी, 2013 के अनुसार) हो गया है, जो पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सबसे अधिक है।

(ii) बिहार को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रही है और बिहार को आपूर्ति की गई केंद्रीय क्षेत्र ऊर्जा वर्ष 2008-09 में लगभग 8,400 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 10,320 एमयू हो गई है।

(iii) 12वीं योजना के दौरान प्रस्तावित चालू किए जाने वाले केंद्रीय क्षेत्र संयंत्रों से बिहार राज्य को 1,447 मेगावाट का लाभ होने की संभावना है।

(iv) इसके अतिरिक्त, बिहार को 1,980 मेगावाट की एनटीपीसी और बीएसईबी की संयुक्त उद्यम परियोजना से 1,373.5 मेगावाट विद्युत प्राप्त होगी।

(v) योजना आयोग ने राज्य क्षेत्र / संयुक्त उद्यम के दो विद्युत संयंत्रों अर्थात् बरौनी टीपीएस यूनिट 6 व 7 (2 x 105 मेगावाट) और मुजफ्फरपुर यूनिट 1 व 2 (2 x 110 मेगावाट) के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 1,053 करोड़ रु0 स्वीकृत किए हैं, जिन्हें योजना आयोग की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत लिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 921.

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति

921. श्री ए.इलावरासन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस पहल से तेल क्षेत्र की व्यावहारिकता को संकट में डालने वाली ईंधन की कमी की समस्या सहित इस क्षेत्र की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में जनवरी, 2013 में एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। सलाहकार समूह का गठन करने के आदेश की प्रति अनुबंध पर संलग्न है।

विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर आवधिक रूप से चर्चा तथा विचार-विमर्श करने और ईंधन की कमी सहित अनेक समस्याएं, जिनका विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना किया जा रहा है, को सुलझाने हेतु विभिन्न मामलों का समाधान करने के लिए क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के उपाय सुझाने हेतु एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 5.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 921 के भाग(क)से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

फा. सं. 2/19/2009-पी एंड पी
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
(योजना प्रभाग)

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 31 जनवरी 2013

कार्यालय आदेश

विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर आवधिक रूप से चर्चा और विचार-विमर्श करने तथा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने का सुझाव देने के लिए विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में सलाहकार समूह का गठन किया गया है। समूह में निम्नलिखित शामिल हैं-

1. अध्यक्ष: विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

सदस्य:

2. सचिव विद्युत

3. अध्यक्ष (सीईए)

4. श्री साइरस मिस्त्री, अध्यक्ष, टाटा ग्रुप -पावर प्रोजेक्ट्स

5. श्री अनिल अम्बानी, अध्यक्ष, एडीएजी

6. श्री सुधीर मेहता, अध्यक्ष, टोरेन्ट ग्रुप

7. श्री मनोज गौड़, कार्यपालक अध्यक्ष एवं सीईओ, जे पी ग्रुप।

8. श्री आर.एन. नायक, सी.एम.डी., पावर ग्रिड कोरपोरेशन इण्डिया लिमिटेड।

9. श्री एस.के. सुनी, सीईओ, पोसोको

10. श्री प्रतीप चौधरी, अध्यक्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया।

11. सुश्री चंदा कोच्चर, एमडी और सीईओ, आईसीआईसीआई बैंक।

12. श्री बी.पी. राव, सी.एम.डी., भेल।

13. श्री बाबा एन. कल्याणी, अध्यक्ष, कल्याणी ग्रुप (भारत फोर्ज लिमिटेड)

14. डॉ. आर.के. पचौरी, महानिदेशक, टेरी।

15. श्री आर.वी. साही, भूतपूर्व सचिव, विद्युत, भारत सरकार।

16. श्री पी. के. सेन गुप्ता, भूतपूर्व अध्यक्ष, सी.आई.एल।

17. श्री विश्वनाथ आनंद, भूतपूर्व सचिव, एम.ओ.ई एण्ड एफ, भारत सरकार ।

18. श्री विनायक चटर्जी, अध्यक्ष, फीडबैक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड ।

19. श्री विवेक पंडित, मैककिन्से एन्ड कम्पनी।

20. अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, विद्युत उत्पादक एसोसिएशन(पदनाम द्वारा)

21. श्री हैरी धाल, महानिदेशक-आईपीपीएआई।

22. श्री जी.एम. राव, अध्यक्ष- जीएमआर

2. विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव स्थायी रूप से आमंत्रित किए जाएंगे।

3. समूह को केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण (सीईए) द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी जो समूह को इसके कार्यों को सहज रूप से करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा। कु. नीरजा माथुर, मुख्य अभियंता, सीईए समूह के सचिव के रूप में कार्य करेंगी।
4. समूह के सदस्य किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक के पात्र नहीं होंगे, परंतु बाहर के सदस्य, जो किसी संगठन में कार्य नहीं कर रहे हैं, को नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य टीए एवं डीए का भुगतान किया जाएगा। व्यय विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2012-13 की मांग संख्या 75 के अंतर्गत प्रमुख शीर्ष 3451, सचिवालय-आर्थिक सेवा, 00.090 सचिवालय (लघु शीर्ष), 03 विद्युत मंत्रालय, 03.00.11 घरेलू यात्रा व्यय के नामे डाला जाएगा।
5. इसे माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

ह0

(मनोरंजन कुमार)
आर्थिक सलाहकार

प्रति

1. सलाहकार समूह के सभी सदस्य
2. सलाहकार समूह के सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:-

विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव
सचिव (विद्युत) के पीपीएस
अध्यक्ष, के.वि.प्रा., नई दिल्ली
अपर सचिव(एएल)/अपर सचिव(डीसी)
सभी संयुक्त सचिव/आर्थिक सलाहकार
भुगतान एवं लेखा कार्यालय, विद्युत मंत्रालय

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-922 .

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

वर्तमान वर्ष में विद्युत उत्पादन

922. श्री अम्बेथ राजनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चालू वित्त वर्ष में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है;
(ख) क्या यह चालू वित्त वर्ष 2012-13 के लिए मेगावाट में निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुरूप है;
(ग) यदि हां, तो सभी स्रोतों से उत्पादित बिजली का ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) मेगावाट (एमडब्ल्यू) का तात्पर्य उत्पादन स्टेशन की क्षमता से है, उत्पादन स्टेशन से वास्तविक विद्युत उत्पादन को मिलियन यूनिट (एमयू) में व्यक्त किया जाता है। उत्पादन लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न परम्परागत स्रोतों से उत्पादन लक्ष्य 9,30,000 मिलियन यूनिट (एमयू) निर्धारित किया गया है। देश में वर्ष 2012-13 (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक) के दौरान विभिन्न परम्परागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात् ताप, हाइड्रो, न्यूक्लियर तथा भूटान से जल विद्युत के आयात से सकल विद्युत उत्पादन 7,71,866 एमयू के लक्ष्य की तुलना में 7,62,668 एमयू है जोकि 98.8% है। स्रोत-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

स्रोत	2012-13		अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013	
	लक्ष्य	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धि
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
थर्मल	7,67,275	6,30,791	6,31,437	100.1
न्यूक्लियर	35,200	28,713	27,450	95.6
हाइड्रो	1,22,045	1,07,191	99,071	92.4
भूटान से आयात	5,480	5,171	4,710	91.1
कुल	9,30,000	7,71,866	7,62,668	98.8

न्यूक्लियर में कम उत्पादन, कुडनकुलम न्यूक्लियर विद्युत परियोजना को शुरू करने में विलम्ब के कारण हैं। भूटान से आयात सहित हाइड्रो में कम उत्पादन दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खराब मानसून के कारण हैं।

वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान पूरी की गई व्यस्ततम विद्युत की मांग 1,23,294 मेगावाट है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-923 .

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

सबके लिए बिजली

923. श्री राम कृपाल यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2012 तक "सबके लिए बिजली" के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है:

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2005 में शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) अत्यंत धीमी गति से चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश भर में तथा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों, जो प्रत्येक गांव तथा प्रत्येक व्यक्ति को बिजली उपलब्ध कराने में पिछड़ रहे हैं. में इस योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) भारत सरकार ने ग्रामीण घरों तक बिजली पहुँचाने की व्यवस्था करने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण के सृजन हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की शुरुआत की थी। इस स्कीम के अंतर्गत, 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण और 2,74,98,652 गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। 31.01.2013 तक की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 1,06,474 यूई गांवों, 2,87,827 पीई गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं और 2,05,15,472 बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी किए गए हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए राज्य-वार लक्ष्य एवं उपलब्धि **अनुबंध** में दी गई है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित भारत निर्माण लक्ष्य, अर्थात् मार्च, 2012 तक 1 लाख गांवों तथा 1.75 करोड़ बीपीएल घरों का विद्युतीकरण, प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में प्रस्तावित तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को 10वीं और 11वीं योजना के दौरान मंजूरी दी गई थी। 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत, शेष गांवों और आवासों/टोलों/माजरो को शामिल करते हुए बिहार में 11 पूरक परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश में 22 पूरक परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। विद्युत मंत्रालय और रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, जोकि आरजीजीवीवाई के लिए नोडल एजेंसी है, बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा के राज्यों में कार्य की प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहे हैं और परियोजनाओं के द्रुत कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार की मदद कर रहे हैं।

राज्यसभा में दिनांक 05.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 923 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों का राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि, आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का तीव्र विद्युतीकरण और बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी किए जाने का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण		आंशिक विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण		बीपीएल घर	
			कवरेज**	संचयी उपलब्धि (31.01.2013 तक)	कवरेज**	संचयी उपलब्धि (31.01.2013 तक)	कवरेज**	संचयी उपलब्धि (31.01.2013 तक)
1	आंध्र प्रदेश*	26	0	0	27477	26756	2484665	2783390
2	अरुणाचल प्रदेश	16	2106	1560	1760	904	40726	24615
3	असम	23	8326	7990	12984	12197	1150597	882554
4	बिहार	54	23850	22565	19244	4990	5658692	2305704
5	छत्तीसगढ़	18	1594	941	17291	11881	987834	944103
6	गुजरात*	25	0	0	17667	16317	742094	827788
7	हरियाणा*	21	0	0	6511	4687	257273	194461
8	हिमाचल प्रदेश	12	95	83	10650	11198	13196	14753
9	जम्मू एवं कश्मीर	14	239	173	4442	2767	81217	51012
10	झारखण्ड	22	19071	18082	7106	5728	1803377	1283770
11	कर्नाटक	27	61	62	28119	24671	978219	856401
12	केरल*	14	0	0	1272	181	74571	52993
13	मध्य प्रदेश	52	843	566	49537	23229	1817544	942734
14	महाराष्ट्र*	35	0	0	41739	36713	1202882	1180284
15	मणिपुर	9	882	616	1378	555	107369	28814
16	मेघालय	7	1866	1606	3239	2127	109696	83067
17	मिजोरम	8	137	94	570	346	27417	15144
18	नागालैण्ड	11	105	84	1140	1060	69899	36062
19	ओडिशा	32	14715	14324	29324	24368	3045979	2802221
20	पंजाब*	17	0	0	11840	0	148860	79104
21	राजस्थान	40	4339	4102	34783	32294	1224417	1120242
22	सिक्किम	4	25	25	418	382	11458	9695
23	तमिलनाडु*	29	0	0	10738	9673	527234	501202
24	त्रिपुरा	4	148	143	658	594	107506	97625
25	उत्तर प्रदेश	86	28439	27762	22980	2982	1907419	1042593
26	उत्तराखण्ड	13	1512	1511	9160	9221	238522	234593
27	पश्चिम बंगाल	29	4442	4185	24309	22006	2679989	2120548
	कुल	648	112795	106474	396336	287827	27498652	20515472

* आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं तमिलनाडु राज्यों में, इन राज्यों द्वारा डीपीआर में कोई गैर-विद्युतीकृत गांव प्रस्तावित नहीं किया गया था। तथापि, इन राज्यों में पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का तीव्र विद्युतीकरण किया जा रहा है।

** आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत स्वीकृत 72 परियोजनाओं के 1909 गैर/निर्विद्युतीकृत गांव, 53505 आंशिक विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण और 4559141 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

राज्य सभा
अतारंकित प्रश्न संख्या-924 .
जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

+924. श्री ओम प्रकाश माथुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया है; और
- (ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 4,339 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 34,783 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण और 12,24,417 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु राजस्थान की 40 परियोजनाओं (10वीं योजना में 25 परियोजनाएं एवं 11वीं योजना में 15 परियोजनाएं) को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत, संचयी रूप से 31.01.2013 के अनुसार 4,102 यूई गांवों, 32,294 पीई गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और 11,20,242 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। राजस्थान राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कवरेज एवं उपलब्धियों का परियोजना-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कुल 2,213 यूई गांवों और 14,829 पीई गांवों को निम्नानुसार विद्युतीकृत किया गया है:

वर्ष	गैर-विद्युतीकृत गांव	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव
2009-10	773	4417
2010-11	1258	7348
2011-12	182	3064
कुल	2213	14829

(ग) सरकार ने निधियों की उपलब्धता के अनुसार शेष गांवों/वासस्थलों और बीपीएल परिवारों को कवर करने के लिए 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखे जाने का प्रस्ताव किया है।

राज्यसभा में दिनांक 05.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 924 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

राजस्थान में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण और बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने का परियोजना-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	कवरेज			संचयी उपलब्धि (31-01-2013)		
		यूई/डीई गांव	पीईवी	बीपीएल एच/एच	यूई/डीई गांव	पीईवी	बीपीएल एच/एच
Xवीं योजना							
1	अजमेर	14	1011	18835	14	921	18835
2	चित्तौड़गढ़	4	0	58	4	0	58
3	डूंगरपुर	100	754	34797	100	754	36050
4	झुंझनु	0	855	9494	0	787	9494
5	राजसमंद	132	841	43607	132	834	43607
6	सीकर	13	973	14368	13	884	14368
7	उदयपुर	46	0	52	46	0	52
8	अलवर	47	1882	42000	47	1853	42000
9	बुंदी	68	771	22464	68	662	23433
10	दौसा	34	991	29396	34	815	29396
11	धौलपुर	162	0	1759	162	0	1759
12	करौली	9	0	78	9	0	78
13	कोटा	38	767	25169	38	691	25169
14	बीकानेर	180	587	30744	180	587	30744
15	चुरू	6	843	35298	6	843	35298
16	हनुमानगढ़	46	0	3133	46	0	3133
17	जैसलमेर	98	348	7094	98	322	7094
18	जैसलमेर	55	0	35	55	0	35
19	जालौर	30	667	36589	30	667	36589
20	जोधपुर	173	885	21198	173	885	21198
21	नागौर लाडनू	0	97	2814	0	97	2638
22	सिरोही	8	447	8246	8	447	8246
23	श्रीगंगानगर	111	0	4000	111	0	4000
24	भीलवाड़ा	104	1589	49510	104	1589	49530
25	झालावार	169	1293	45827	169	1293	45827
	उप जोड़	1647	15601	486565	1647	14931	488631
XIवीं योजना							
1	बांसवाड़ा	446	967	74493	357	689	57783
2	चित्तौड़गढ़ (सप.)	207	1977	56141	196	1896	63647
	नागौर	0	0	37762	0	0	37112
3	उदयपुर (सप.)	374	1793	104904	307	1701	97884
	बारमेड़	0	0	60124	0	0	47312
4	हनुमानगढ़ (सप.)	132	1576	39319	132	940	36091
	पाली	0	0	67945	0	0	8220
5	एस. गंगानगर (सप.)	179	2505	35372	178	2264	40647
	बारन	0	0	31358	0	0	16582
	भरतपुर	0	0	12557	0	0	9027
6	धौलपुर (सप.)	131	491	17284	88	266	10100
7	जयपुर	47	2030	39356	47	1829	40405
8	करौली (सप.)	65	617	39052	66	623	40845
9	एस. माधौपुर	76	613	28438	75	608	30499
10	टोंक	140	878	19966	140	869	21427
11	बारन	86	973	9812	87	949	9814
12	बारमेड़	668	1230	0	647	1200	0
13	भरतपुर	96	1265	30674	95	1264	30921
14	नागौर	25	1352	4707	25	1352	4707
15	पाली	20	915	28588	15	913	28588
	उप जोड़	2692	19182	737852	2455	17363	631611

40	कुल जोड़	4339	34783	1224417	4102	32294	1120242
----	----------	------	-------	---------	------	-------	---------

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-925
जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

ग्रिड का बार-बार फेल हो जाना

925. श्री प्रकाश जावडेकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 2012 में उत्तर पूर्वी ग्रिड ठप्प हो गया था:

(ख) यदि हां, तो ग्रिड ठप्प होने के कारण हुई क्षति का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर में ग्रिड के इस तरह बार-बार ठप्प पड़ने को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाने का प्रस्ताव किया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): 14 दिसंबर, 2012 तथा 29 दिसंबर, 2012 को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में बाधा उत्पन्न हुई थी । 14 दिसंबर तथा 29 दिसंबर, 2012 को क्रमशः 553 मेगावाट तथा 603 मेगावाट की उत्पादन हानि हुई थी जबकि, भार हानि क्रमशः 923 मेगावाट और 954 मेगावाट थी । दोनों अवसरों पर बाधा लोड-जेनरेशन के बेमेल होने के कारण आई थी ।

(ग) 30 तथा 31 जुलाई, 2012 की प्रमुख ग्रिड बाधाओं के तुरंत पश्चात विद्युत मंत्रालय ने अध्यक्ष, सीईए की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी । जांच समिति ने कई सिफारिशों की थीं ताकि भविष्य में ऐसी ग्रिड बाधाओं को होने से रोका जा सके । विद्युत मंत्रालय ने जांच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखा परीक्षा; जोन-3 फिलासफी की समीक्षा; अनिर्धारित अंतः परिवर्तन प्रणाली की समीक्षा; आई लैडिंग स्कीमों का प्रतिपादन; इत्यादि शामिल है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र सहित विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा विभिन्न मामलों पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में याचिकाएं भी दायर की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संकुलता प्रभार प्रक्रिया में संशोधन, फ्रिक्वेंसी बैंड को और ज्यादा सख्त बनाना, सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन, उत्पादन से प्रारंभिक परिणाम इत्यादि शामिल हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-926

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

दक्षिणी ग्रिड को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ना

926. श्री बैष्णव परिडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के प्रमुख भागों में ब्लैक आउट पर नियंत्रण पाने के लिए दक्षिणी ग्रिड को युद्ध स्तर पर राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उपभोक्ता राज्यों को किसी प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं जिससे बिजली की खपत को सीमा के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके और किसी प्रकार का उल्लंघन जिससे विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी ब्लैक आउट की स्थिति पैदा होगी, को गंभीरता से लिया जाएगा;और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): रायचूर (कर्नाटक) से शोलापुर (महाराष्ट्र) तक दो 765 केवी एस/सी पारेषण लाइनें निर्माणाधीन हैं । एक लाइन का निर्माण पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जबकि, दूसरी लाइन का निर्माण मैसर्स रायचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (आरएसटीसीएल) द्वारा किया जा रहा है । इन दो 765 केवी लाइनों के पूरा होने के साथ दक्षिणी ग्रिड सिंक्रोनस तरीके से शेष राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जुड़ जाएगा । इन दोनों लाइनों को 2014 तक पूरा किया जाना निर्धारित है ।

(ग) और (घ): केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा जारी किए गए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) की धारा 5.4.2 की उपधारा (क) (ते) के अनुसार, क्षेत्र के घटक राज्यों को उनके कार्यक्रम के अनुसार ग्रिड से विद्युत की निकासी को बनाए रखना होता है और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी), जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के एकीकृत प्रचालन के लिए शीर्ष निकाय है और उन राज्यों को नियमित सन्देश भेजता है जो कि उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्युत की निकासी को नहीं बनाए रखते हैं । ग्रिड अनुशासन के इस प्रकार के उल्लंघन को सीईआरसी के नोटिस में भी लाया जाता है । इसके अतिरिक्त, सीईआरसी ने दिनांक 16.06.2012, 30.07.2012 और 17.08.2012 के आदेश के माध्यम से भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और विद्युत अधिनियम, 2003 की शर्तों के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र के घटकों द्वारा अधिक निकासी को रोक करके और उचित भार प्रबंधन को प्रभावी बनाते हुए संपूर्ण नए ग्रिड की ग्रिड सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उत्तरी क्षेत्र के घटकों को निर्देश दिया है।

दोषी राज्यों द्वारा उल्लंघन किए जाने पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 29,142 और 143 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-927 .

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

एन.टी.पी.सी. द्वारा ईंधन का आयात

927. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पादन लागत में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकियों के वैश्विक विकास के दृष्टिगत ऐसी प्रौद्योगिकियों के अभिप्रेत हमारे अभियांत्रिकी डिजाइनों को उन्नत बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए एक निर्दिष्ट कार्य-बल गठित किया है;

(ख) क्या एस.टी.सी., एम.एम.टी.सी. आदि के माध्यम से आयात की मौजूदा व्यवस्था के बदले एन.टी.पी.सी. द्वारा सीधे ईंधन (कोयला) का आयात एक लागत-प्रभावी विकल्प होगा;

(ग) क्या एन.टी.पी.सी. ने यूरोप, आस्ट्रेलिया आदि में अच्छे कोयला संयोजन वाले विद्युत संयंत्र उपार्जित किए हैं; और

(घ) क्या विदेशों में खानों का स्वामित्व लागत-कटौती उपायों की दिशा में पुर्नानुकूलित और लक्षित होगा?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) विद्युत मंत्रालय ने उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से अपने अभियांत्रिकी डिजाइनों का उन्नयन करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नामित कार्यबल का गठन नहीं किया है। तथापि, प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी डिजाइनों का उन्नयन एक निरंतर एवं चलते रहने वाली प्रक्रिया है। दक्षता में सुधार लाने, ईंधन खपत में कमी करने तथा समग्र रूप से ईंधन की लागत कम करने की दृष्टि से सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपनाई गई है। परियोजना निष्पादन की अवधि में कमी लाने की दृष्टि से मानकीकरण भी किया जा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 500 मेगावाट सब-क्रिटिकल यूनितों के मुख्य संयंत्र उपकरण का मानक डिजाइन दस्तावेज तैयार किया गया है तथा सुपर-क्रिटिकल यूनितों का मानक तकनीकी विशेषताओं पर दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।

एनटीपीसी लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) तथा इंदिरा गांधी परमाणु

-2-

अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) ने 300 केजी/सीएम² तथा 7000 सी तापमान के स्टीम पैरामीटरों की प्रौद्योगिकी के विकास में सहयोग देने के लिए अगस्त, 2010 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य 7 वर्ष की अवधि में, जिसमें डिजाइन तथा विकास के ढाई वर्ष को शामिल करते हुए 800 एमडब्ल्यूई एयूएससी कोल फायर्ड यूनिट का निष्पादन करना है।

(ख) : एनटीपीसी 2005-06 से एमएमटीसी/एसटीसी के माध्यम से आयातित कोयले की खरीद कर रही थी जो दिसंबर, 2011 तक जारी रही। तत्पश्चात्, एनटीपीसी फरवरी, 2012 से अर्थात् लगभग एक वर्ष से आयातित कोयले की खरीद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के माध्यम से सीधे कर रही है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कि कौन-सा विकल्प बेहतर रूप से लागत-प्रभावी है, जल्दबाजी होगा।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : जहां तक एनटीपीसी का संबंध है, अब तक इसकी विदेश में अपनी कोई खान नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-928 .

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

कृषि और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पृथक विद्युत वितरण लाइनें

928. श्री संजय राउत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गुजरात राज्य सरकार के पास कृषि और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए पृथक विद्युत वितरण लाइनें हैं;
- (ख) क्या मंत्रालय अन्य राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना चाहता है;
- (ग) यदि हां, तो इस पर कितने व्यय का अनुमान है और इसका वित्त-पोषण किस प्रकार किया जाएगा; और
- (घ) क्या अनेक वितरण लाइनों से बिजली चोरी में बढ़ोतरी होगी तथा रख-रखाव की कीमत में वृद्धि होगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 में शुरू की गई उनकी "ज्योतिग्राम योजना" नामक एक स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा ग्रामीण वितरण फीडर्स को, ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-कृषीय (आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक) उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए ज्योतिग्राम फीडर्स, तथा कृषि उपभोक्ताओं को 3-फेज विद्युत आपूर्ति एवं खेतों में रह रहे किसानों को विशेष डिजाइन ट्रांसफार्मरों के माध्यम से सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति के लिए कृषि फीडर्स में पृथक किया गया है।
- (ख) से (घ) विद्युत मंत्रालय के पास वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-929 .

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

विभिन्न राज्यों में बिजली की मांग

929. श्री तरुण विजय:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विभिन्न राज्यों में बिजली की मांग और बिजली आपूर्ति की वास्तविक स्थिति में कितना अंतर है;
- (ख) कितने राज्य अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं और परियोजना-वार उनके ऊर्जा उत्पादन तथा प्रति यूनिट लागत का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सौर तथा पवन ऊर्जा के अंतिम प्रयोक्ता को कर में कोई राहत प्रदान की जाती है;
- (घ) यदि हां, तो राहत की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) राज्य-वार ऐसे लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक) के दौरान व्यस्ततम और ऊर्जा दोनों के संबंध में देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग तथा विद्युत आपूर्ति में कमी के प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।
- (ख) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, फेज-1 के बैच-1 के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत चालू की जा चुकी सौर परियोजनाओं के साथ-साथ माइग्रेशन स्कीम के अंतर्गत सौर पीवी परियोजनाओं और कुल पवन संस्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है। इन यूनिटों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप में नहीं दिया जाता है। सौर ऊर्जा की प्रति यूनिट औसत लागत 7.49 रुपए/कि.वा. घंटा है।

(ग) से (ड) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, सौर तथा पवन ऊर्जा के अंतिम प्रयोगकर्ताओं को टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाती है।

राज्य सभा में दिनांक 05.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

वर्ष 2012 -2013 की विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

राज्य/ प्रणाली / क्षेत्र	ऊर्जा				अधिकतम			
	अप्रैल, 2012 - जनवरी, 2013				अप्रैल, 2012 - जनवरी, 2013			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिकता / कमी (-)		अधिकतम मांग	अधिकतम पूर्ति	अधिकता / कमी (-)	
	(एम.यू.)	(एम.यू.)	(एम.यू.)	(%)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(मे.वा.)	(%)
चंडीगढ़	1,434	1,434	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	22,827	22,694	-133	-0.6	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	35,828	32,783	-3,045	-8.5	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	7,576	7,342	-234	-3.1	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू एवं कश्मीर	12,792	9,594	-3,198	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	41,747	39,239	-2,508	-6.0	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	45,953	44,299	-1,654	-3.6	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तरप्रदेश	77,497	64,692	-12,805	-16.5	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	9,660	9,064	-596	-6.2	1,757	1,674	-83	-4.7
उत्तरी क्षेत्र	255,314	231,141	-24,173	-9.5	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	14,210	13,968	-242	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	75,423	75,275	-148	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्यप्रदेश	43,770	39,017	-4,753	-10.9	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	104,016	100,539	-3,477	-3.3	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन और दीव	1,567	1,436	-131	-8.4	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	3,643	3,474	-169	-4.6	629	629	0	0.0
गोवा	2,509	2,439	-70	-2.8	491	452	-39	-7.9
पश्चिमी क्षेत्र	245,138	236,148	-8,990	-3.7	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्रप्रदेश	82,067	68,006	-14,061	-17.1	13,974	11,335	-2,639	-18.9
कर्नाटक	54,365	47,104	-7,261	-13.4	10,124	8,458	-1,666	-16.5
केरल	17,649	16,967	-682	-3.9	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	76,560	63,308	-13,252	-17.3	12,606	11,053	-1,553	-12.3
पांडिचेरी	1,938	1,900	-38	-2.0	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	30	30	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	232,579	197,285	-35,294	-15.2	36,934	31,287	-5,647	-15.3
बिहार	12,630	10,800	-1,830	-14.5	2,295	1,784	-511	-22.3
झारखंड	14,464	13,715	-749	-5.2	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	5,801	5,575	-226	-3.9	1,106	1,033	-73	-6.6
ओडिशा	21,234	20,443	-791	-3.7	3,968	3,694	-274	-6.9
पश्चिम बंगाल	35,483	35,230	-253	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	341	341	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान-निकोबार	201	156	-45	-22	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	90,306	86,104	-4,202	-4.7	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	503	472	-31	-6.2	116	114	-2	-1.7
असम	5,544	5,186	-358	-6.5	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	488	462	-26	-5.3	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,510	1,314	-196	-13.0	312	310	-2	-0.6
मिजोरम	339	315	-24	-7.1	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	480	453	-27	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	936	890	-46	-4.9	229	228	-1	-0.4
पूर्वांचल क्षेत्र	9,800	9,092	-708	-7.2	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारत	833,230	759,849	-73,381	-8.8	135,453	123,294	-12,159	-9.0

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणालियां हैं, इनमें विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं बनाती हैं।

टिप्पणी: अधिकतम पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत (पारेषण हानियों सहित) का प्रतिनिधित्व करती हैं। निवल निर्यात को आयातकर्ता राज्यों की खपत में जोड़ा गया है।

राज्य सभा में दिनांक 05.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 929 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

जेएनएनएसएम के बैच- I, फेज- I के अंतर्गत सौर पीवी परियोजनाओं के शुरु होने की स्थिति

(क) रूफटॉप पीवी और लघु सौर विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (आरपीएसएसजीपी)

राज्य-वार:

क्रम सं.	राज्य	पीपीए के अनुसार चालू की जानेवाली सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक रूप से चालू की गई सौर पीवी क्षमता (मेगावाट)	शुरु की जाने वाली शेष क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	10.5	9.75	0.75
2	छत्तीसगढ़	4	4	0
3	हरियाणा	8.8	7.8	1
4	महाराष्ट्र	5	5	0
5	ओडिशा	8	7	1
6	पंजाब	8.5	6	2.5
7	राजस्थान	12	10	2
8	तमिलनाडु	7	5	2
9	उत्तराखण्ड	5	5	0
10	उत्तर प्रदेश	8	7	1
11	झारखण्ड	16	16	0
12	मध्य प्रदेश	5.25	5.25	0
	कुल	98.05	87.80	10.25

परियोजना-वार

क्र.सं..	चालू की गई परियोजनाओं के नाम	राज्य	पीपीए के अनुसार आंबटित सोलर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक तौर पर चालू सोलर पीवी की क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि	चालू किए जाने हेतु शेष क्षमता(मेगावाट)
1.	श्री पावर जेनरेशन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	14-01-2012	-
2.	अमृतजल वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	07-03-2012	-
3.	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	10-01-2012	-
4.	रामकृष्ण इण्डस्ट्रीज	आंध्रप्रदेश	1	1	16-09-2011	-
5.	सिंघाल फोरेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	2	2	15-11-2011	-
6.	छत्तीसगढ़ इन्वेसमेंट लिमिटेड	छत्तीसगढ़	2	2	14-10-2011	-
7.	चन्द्रलीला पावर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	हरियाणा	0.8	0.8	15-01-2012	-
8.	जमील न्यू दिल्ली इंफ्राटक्वर प्राईवेट लिमिटेड	हरियाणा	1	1	27-01-2012	-
9.	एसडीएस सोलर प्राईवेट लिमिटेड	हरियाणा	1	1	21-10-2011	-
10.	सुखवीर सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	हरियाणा	1	1	15-12-2011	-
11.	सी एण्ड एस इलेक्ट्रिक लिमिटेड.	हरियाणा	1	1	28-06-2011	-
12.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड.	महाराष्ट्र	1	1	30-07-2011	-
13.	सेपसेट कन्ट्रक्शन लिमिटेड.	महाराष्ट्र	2	2	16-11-2011	-
14.	सितारा रियल इस्टेट लिमिटेड.	महाराष्ट्र	2	2	16-11-2011	-
15.	एमजीएम मिनरल्स लिमिटेड	ओडिशा	1	1	13-10-2011	-
16.	राजरतना एनर्जी होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	ओडिशा	1	1	30-06-2011	-
17.	एस एन मोहन्ती	ओडिशा	1	1	23-08-2011	-
18.	मोलीसती विनिमेय प्राईवेट लिमिटेड	ओडिशा	1	1	22-12-2011	-
19.	सोमा इन्टरप्राइजेज लिमिटेड	पंजाब	1	1	03-12-2011	-
20.	एईडब्ल्यू इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	05-01-2012	-
21.	एसियन ऐरो- ईडीयू एवीएशन प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	02-12-2011	-
22.	बसन्त इन्टरप्राइजेज	राजस्थान	1	1	13-01-2012	-
23.	जमील न्यू दिल्ली इंफ्राटक्वर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	11-01-2012	-
24.	नवभारत बुल्डकॉन प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	10-02-2012	-
25.	लैंको सोलर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	16-09-201	₹
26.	बी एण्ड जी सोलर प्राईवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1	1	10-06-2011	-
27.	आरएल क्लीन पावर प्राईवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1	1	25-07-2011	-
28.	ग्रेट शाइन होल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1	1	28-01-2012	-
29.	आरवी आकाश गंगा इन्फ्राटक्वर लिमिटेड	उत्तराखंड	2	2	13-01-2012	-
30.	टेक्नीकल एसोसिएट्स लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	2	2	30-01-2012	-
31.	किजाल्क इन्फ्राटक्वर प्राईवेट लिमिटेड	झारखंड	2	2	16-01-2012	-
32.	मेट्रो फ्रोजन फ्रूट एण्ड वेजीटेबल्स लिमिटेड	उत्तराखंड	1	1	09-03-2012	-
33.	आंध्रोमेडा एनर्जी टेकनिकल प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	0.75	0.75	15-03-2012	-

34.	विवेक फर्माकेम (इण्डिया) लिमिटेड	राजस्थान	1	1	10-3-2012	
35.	ईकोएनर्जी आईएनसी	पंजाब				-
36.	सोवोक्स रेनेवेबल्स प्राईवेट लिमिटेड	पंजाब	1	1	16.03.2012	-
37.	जीएस अठवाल एण्ड कंपनी (इंजीनियर्स) प्राईवेट लिमिटेड	पंजाब	1.5	1.5	10.03.2012	-
38.	एमसोन पावर प्राईवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1	1	14.03.2012	
39.	सन एडीसन एनर्जी इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	10.03.2012	-
40.	किशोर इलैक्ट्रो. इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	13.03.2012	-
41.	हरीसंस पावर प्राईवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1	1	14.03.2012	-
42.	गजानन फाइनेनशियल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	14.03.2012	-
43.	ध्रुव मिल्कोज प्राईवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	1	1	13.03.2012	-
44.	फोटोन एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	15.03.2012	-
45.	डेंटे एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	2	2	16.03.2012	-
46.	तायल एण्ड कं.	हरियाणा	1	1	13.03.2012	-
47.	वीकेजी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	हरियाणा	1	1	15.03.2012	-
48.	एच.आर. मिनिरल्स एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड	हरियाणा	1	1	10.03.2012	-
49.	कारलिल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	पंजाब	1.5	1.5	24.02.2012	-
50.	अबकस होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	ओडिशा	1	1	13.03.2012	-
51.	भवानी इंजीनियरिंग	आंध्रप्रदेश	1	1	14.03.2012	-
52.	पीसीएस प्रीमियर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	झारखंड	2	2	24.02.2012	-
53.	जय एस टेक्नोलोजीस लिमिटेड	उत्तराखंड	2	2	13.03.2012	-
54.	सोवोक्स रेनेवेबल्स प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	13.03.2012	-
55.	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	1	1	15.03.2012	-
56.	न्यू ईरा इन्वाइरो वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	झारखंड	2	2	31.03.2012	-
57.	प्रीमियर सोलर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	झारखंड	2	2	30.03.2012	-
58.	कनफ्लक्स इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	1	16.03.2012	-
59.	एनरटेक इंजीनिसरिंग प्राईवेट लिमिटेड	झारखंड	2	2	20.04.2012	-
60.	पेनटाइम फार्निश कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	ओडिशा	1	1	16.03.2012	-
61.	श्री महावीर फेरो एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड	ओडिशा	1	1	15.03.2012	-
62.	केवीआर कन्सट्रक्शन्स	झारखंड	2	2	21.04.2012	-
63.	एकेआर कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड	झारखंड	2	2	07.06.2012	-
64.	सैमेग इंफ्राटक्चर प्राईवेट लिमिटेड	झारखंड	2	2	16.06.2012	-
65.	प्रायपस इंफ्राटक्चर लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	2	2	16.03.2012	-
66.	अडोरा एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	मध्यप्रदेश	2	2	19.06.2012	-
67.	एसआर डेवलपस प्राईवेट लिमिटेड	मध्यप्रदेश	1.25	1.25	13.06.2012	-
68.	शिव-वाणी एनर्जी लिमिटेड	मध्यप्रदेश	2	2	16.06.2012	2
69.	आयरन एण्ड स्टील्स लिमिटेड	ओडिशा	1	-		1
70.	नोएल मीडिया एण्ड एडवर्टाइजिंग प्राईवेट	तमिलनाडु	1	-		1

	लिमिटेड					
71.	ईस्टर्न बियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	1	-		1
72.	गंगास इण्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	-		1
73.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पंजाब	1	-		1
74.	रिलायबल मेनपावर सोलूसन्स लिमिटेड	हरियाणा	1	-		1
75.	सोलर सेमीकण्डक्टर प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	0.75	-		0.75
76.	जेमिनी जीअस एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	तमिलनाडु	1	-		1
77.	इण्टरप्राईजेज विजनेस सोलूसन्स	पंजाब	1.5	-		1.5
78.	रेज पावर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	1	-		1
		कुल	98.05	87.80		10.25

* ग्रिड से परियोजना के सिंक्रोनाईजेशन करने पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर 19.09.2011 में परिवर्तन किया गया और प्रचालनात्मक मामलों पर विशेष समिति द्वारा समीक्षा की गई थी ।

(ख) i. माईग्रेशन स्कीम के अंतर्गत ग्रिड सोलर पीवी परियोजनाएं

क्र.सं.	चालू की गई परियोजनाओं के नाम	राज्य	पीपीए के अनुसार आंबटित सोलर पीवी क्षमता(मेगावाट)	वास्तविक तौर पर चालू सोलर पीवी की क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने हेतु शेष क्षमता(मेगावाट)
1	क्लोवर सोलर प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई	महाराष्ट्र	2	2	-
2	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन क. लिमिटेड, मुम्बई	महाराष्ट्र	4	4	-
3	वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई	महाराष्ट्र	5	5	-
4	अजूर पावर (पंजाब) प्राईवेट लिमिटेड., अमृतसर प्राईवेट लिमिटेड., गुडगांव , हरियाणा	पंजाब	2	2	-
5	एईएस सोलर एनर्जी	राजस्थान	5	5	-
6	एस्टन फील्ड सोलर (राजस्थान) प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	-
7	कोमेट पावर प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई	राजस्थान	5	5	-
8	मोजर बीअर फोटो वोल्टेक लिमिटेड., नई दिल्ली	राजस्थान	5	5	-
9	ओपीजी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड., चेन्नई, तमिलनाडु	राजस्थान	5	5	-
10	रीफेक्स रेफ्रीजरेन्ट्स लिमिटेड, चेन्नई	राजस्थान	5	5	-
11	स्वीस पार्क वेनीज्या प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	-
12	इण्टरप्राईज विजनेस सोलूसन्स	राजस्थान	5	-	5
13	इण्टेगरा लिमिटेड	राजस्थान	1	-	1
	कुल		54	48	6

(ख) ii. माईग्रेशन स्कीम के अंतर्गत ग्रिड सौर ताप परियोजनाएं

क्र.सं.	चालू की गई परियोजनाओं के नाम	राज्य	पीपीए के अनुसार आबंधित सोलर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक तौर पर चालू सोलर पीवी की क्षमता (मेगावाट)	चालू किए जाने हेतु शेष क्षमता (मेगावाट)
1.	एकमे टेसी पावर लिमिटेड, गुडगांव	राजस्थान	10	2.5	7.5
2.	डालमियां सोलर पावर लिमिटेड	राजस्थान	10	-	10
3.	इण्टेगरा लिमिटेड	राजस्थान	10	-	10
	कुल		30	2.5	27.5

। कुछ परियोजनाओं को प्रदर्शित नहीं किया गया है क्योंकि आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) iii. फेज-I , बैच-I के अंतर्गत ग्रिड सोलर पीवी परियोजनाएं

क्र.सं.	चालू की गई परियोजनाओं के नाम	राज्य	पीपीए के अनुसार आबंटित सोलर पीवी क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक तौर पर चालू सोलर पीवी की क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि	चालू किए जाने हेतु शेष क्षमता (मेगावाट)
1.	आफताब सोलर प्राईवेट लिमिटेड	ओडिशा	5	5	07/02/2012	-
2.	एलेक्स स्पेक्ट्रम रेडिएशन प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	21/02/2012	-
3.	अमृत एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	02/02/2012	-
4.	अजूर पावर (राजस्थान) प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	01/01/2012	-
5.	सीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	तमिलनाडु	5	5	29/03/2012	-
6.	डीडीई रेनेवेबल एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	14/02/2012	-
7.	इलैक्ट्रोमेक मशीनेक प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	01/02/2012	-
8.	ईएमसी लिमिटेड	उत्तर प्रदेश	5	5	04/03/2012	-
9.	फाईनहोप एलाईड इंजीनियरिंग प्राईवेट	राजस्थान	5	5	07/02/2012	-
10.	ग्रीनटेक पावर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	08/02/2012	-
11.	इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	राजस्थान	5	5	02/02/2012	-
12.	कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कर्नाटक	5	5	25/06/2012	-
13.	खया सोलर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	28/01/2012	-
14.	महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड	राजस्थान	5	5	07/01/2012	-
15.	महीन्द्रा सोलर वन प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	03/01/2012	-
16.	न्यूटन सोलर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	09/02/2012	-
17.	नोर्थवेस्ट एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	07/01/2012	-
18.	ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड	राजस्थान	5	5	10/01/2012	-
19.	प्रेसीसन टेकनिक प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	22/03/2012	-
20.	पुंजलॉयड सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	08/01/2012	-
21.	सैधाम ओवरसीज प्राईवेट	राजस्थान	5	5	30.01.2013	

	लिमिटेड					
22.	सैसुधीर एनर्जी लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	5	5	05/01/2012	-
23.	एसईआई सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	01/01/2012	-
24.	वासवी सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड	राजस्थान	5	5	02/02/2012	-
25.	विरज रेनेवेबल एनर्जी	राजस्थान	5	5	05/01/2012	-
26.	वेल्सपन सोलर एपी प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	5	5	01/01/2012	-
27.	रितविक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	आंध्रप्रदेश	5	-	-	5
28.	फायर स्टोन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र	5	-	-	5
		कुल	140	130	-	10

पवन ऊर्जा क्षमता प्रतिस्थापना (मेगावाट)
(जनवरी, 2013 तक)

क्र.सं.	राज्य	कुल
01	आंध्रप्रदेश	435.45
02	गुजरात	3092.88
03	कर्नाटक	2113.35
04	केरल	35.10
05	मध्यप्रदेश	386.00
06	महाराष्ट्र	2975.90
07	राजस्थान	2355.10
08.	तमिलनाडु	7153.63
09	अन्य	4.30
	कुल	18551.70

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-930

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन

930. श्री राजकुमार धूत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने देश में राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन के लिए हाल ही में बैंकों से चर्चा की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन चर्चाओं का क्या परिणाम निकला; और
- (घ) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या भूमिका है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 08.02.2013 को बैंकर्स के साथ, राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इस बैठक में, स्कीम के महत्व तथा कार्यान्वयन की अत्यावश्यकता पर पुनः बल दिया गया था।

(घ) राज्य सरकारों की भूमिका इस प्रकार है:-

- (i) 31 मार्च, 2012 को बकाया अल्पकालिक दायित्वों (एसटीएल) के 50% दायित्वों को राज्य सरकारों द्वारा लिया जाना है। इसे सर्वप्रथम, डिस्कॉम द्वारा सहभागी ऋणदाताओं को राज्य सरकार की गारंटी से जारी किए जाने वाले बॉन्डों में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस ऋण (एसटीएल का 50%) के लिए, वित्तीय ऋण को लेने की गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए सहभागी ऋणदाताओं के पक्ष में चरणबद्ध तरीके से विशेष प्रतिभूतियों को 2-5 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। मूलधन पुनः अदायगी के लिए 3-5 वर्षों के ऋण स्थगन के साथ डोर-टू-डोर परिपक्वता 15 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
- (ii) राज्य सरकार डिस्कॉम को इस भाग के ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
- (iii) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विशेष प्रतिभूतियां संबंधित राज्यों के एफआरबीएम अधिनियमों में निर्धारित लक्ष्यों के भीतर हों तथा यदि एफआरबीएम लक्ष्यों के अंतर्गत ऋण-जीएसडीपी अनुपात सहित वित्त की उपलब्धता हो तो भी राज्यों को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूला के अनुसार, वार्षिक रूप से निर्धारित अपनी संबंधित निवल उधार सीमा (प्रत्येक संबंधित वित्त की) को बनाए रखने की आवश्यकता है।
